भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2416

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को देय अनुदान

2416. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को आज की तारीख तक देय सभी प्रकार के अनुदानों की वर्ष-वार, क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार मात्रा और ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु को देय अनुदानों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी कारण से अनुदानों के बकाए और बकाया राशियों का आज की तारीख तक क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार मात्रा और ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राशियों को जारी करने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): व्यय विभाग, वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर, नोडल मंत्रालयों से अनुशंसाएं प्राप्त होने पर तमिलनाडु राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करता है। अनुदान जारी करना संबंधित अनुदान श्रेणियों के मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी किए गए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**श्रेणियां**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	पश्चांतरण राजस्व घाटा[#]	2204	0	0	0	0
2	स्थानीय सरकार को अनुदान[*]	6530	4624	5244	3677	4646

3	आपदा जोखिम प्रबंधन अनुदान**	1382	1168	1007	1881	2150
कुल योग		**10117**	**5792**	**6251**	**5558**	**6796**

#15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए तमिलनाडु को कोई अनुदान देने की अनुशंसा नहीं की गई।

*इसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदान शामिल हैं।

**इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, राज्य आपदा शमन कोष, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष शामिल हैं।

15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) की अधिनिर्णय अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2026-27 से 2030-31 की अधिनिर्णय अवधि के लिए लागू की जा रही है। वर्ष 2026-27 में, तमिलनाडु राज्य को 16वें वित्त आयोग के सहायता अनुदान जारी करने के लिए नोडल मंत्रालयों से कोई अनुशंसा लंबित नहीं है।

***